2 युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से बदली स्कूलों की रौनक

5 स्वर्ण अक्षरों से दर्ज है सुंदरलाल पटवा का नाम

7 जगन्नाथ रथयात्रा हादसा प्रबंधन की भूल का परिणाम

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 09 प्रति सोमवार, 7 जुलाई 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

हेमंत खंडेलवाल बने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष : संगठन में सामंजस्य और गुटबाजी से निपटना बड़ी चुनौती

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर

मध्यप्रदेश भाजपा को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। पार्टी आलाकमान ने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। वे वीडी शर्मा का स्थान लेंगे, जो लंबे समय से अतिरिक्त कार्यकाल पर चल रहे थे। पार्टी के अंदर यह बदलाव कई दिनों से चर्चा में था, लेकिन अंतिम निर्णय को लेकर असमंजस बना हुआ था। खंडेलवाल के नाम की घोषणा के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में

का भरोसा- ये सभी उनकी ताकत हैं। लेकिन साथ ही, गुटबाजी, नाराज नेताओं को साधना और सत्ता-संगठन का संतुलन बनाना उनकी परीक्षा भी है। आने वाले दिनों में प्रदेश भाजपा में और को सक्रिय करने, तथा सत्ता के फैसलों से संगठन को जोड़ने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मानते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद संगठन की भूमिका और भी अहम हो गई है। 2029 की तैयारी और 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना और गुटबाजी को समाप्त करना अनिवार्य होगा।

नाराज नेताओं को मनाना भी चुनौतीपूर्ण

भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लंबे समय से अलग-अलग गुट सक्रिय थे। कई दिग्गज नेता अपने समर्थकों को इस पद पर देखना चाहते थे। लेकिन अंततः खंडेलवाल के नाम पर सहमति बनी। अब नाराज नेताओं को मनाना, उन्हें साथ लेकर चलना और संगठन में सामूहिक नेतृत्व की भावना स्थापित करना खंडेलवाल के लिए अगली बड़ी परीक्षा होगी। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दे रहे छत्तीसगढ़ को विकास के नये आयाम, कानून-व्यवस्था पर भी कसा शिकंजा

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 20 महीने के कार्यकाल में प्रदेश को विकास के नये आयाम देने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं। चाहे किसान हों, आदिवासी समाज, महिलाएं, युवा या व्यापारी वर्ग- साय ने हर वर्ग को राहत देने और अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया है।

बीते डेढ़ वर्ष में मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और

अधोसंरचना विकास पर विशेष फोकस किया।

उनके निर्देश पर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवास निर्माण की गति बढ़ाई गई। गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने का वादा उन्होंने व्यक्तिगत समीक्षा बैठकों में दोहराया। इसी प्रकार, किसानों को समय पर खाद-बीज वितरण, फसल बीमा और समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की गई।

हाल ही में साय सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस वितरण की भी घोषणा कर आदिवासी अंचलों को राहत दी। (शेष पेज 7 पर)

ओबीसी शासकीय सेवकों को पदोन्नति में मिलेगा आरक्षण

कमलनाथ की पहल पर प्रदेश के लाखों युवाओं को मिली राहत, आखिरकार मोहन सरकार को लेना पड़ा पदोन्नति में ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार ने आखिरकार कदम आगे बढ़ा ही दिया। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का मामला लंबे समय से अदालतों में उलझा हुआ था, लेकिन अब सरकार ने

इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि यह फैसला दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की दूरदर्शी पहल का नतीजा है। कमलनाथ सरकार ने अपने 18 माह के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग के हित में कई बड़े निर्णय लिए थे। ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का ऐतिहासिक निर्णय कमलनाथ कैबिनेट ने ही लिया था। उस समय इसे भाजपा नेताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते ओबीसी वर्ग के अधिकारों को वर्षों तक अदालतों में उलझाकर रखा। (शेष पेज 2 पर)

युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से बदली स्कूलों की रौनक

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत खपराखोल शाला में अशोक धत्री और सुनील सिंह पैकरा की पदस्थापना की गई है। इससे पहले इस विद्यालय में नियमित शिक्षक नहीं थे और आसपास के स्कूलों से वैकल्पिक व्यवस्थाओं से पढ़ाई का काम चलाया जा रहा था। नई पदस्थापना के साथ ही विद्यालय में शिक्षा की लौ फिर से प्रज्ज्वलित हो उठी है। नवनियुक्त शिक्षकों ने पदभार ग्रहण करते ही विद्यालय में जान फूंक दी। उन्होंने न केवल कक्षाओं का संचालन शुरू किया, बल्कि गांव में घर-घर जाकर पालकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित भी किया। शिक्षकविहीन स्कूलों की चिंता अब बीते दिनों की बात हो चली है। राज्य शासन द्वारा लागू की गई युक्तियुक्तकरण नीति ने गांव-गांव में शिक्षा की नई उम्मीद जगाई है। बिलासपुर जिला के कोटा विकासखंड का सुदूरवर्ती गांव खपराखोल भी अब इस बदलाव का साक्षी बन गया है। वर्षों से शिक्षकविहीन इस गांव के शासकीय प्राथमिक शाला को अब नियमित शिक्षक मिल चुके हैं, जिससे ग्रामीणों और पालकों में खुशी की लहर है। परिणामस्वरूप, वर्तमान में विद्यालय में 46 विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययनरत हैं और इस वर्ष 7 नए बच्चों ने स्कूल में प्रवेश लिया है।

विद्यालय में अब बच्चों की हँसी, पाठों की गूंज और सीखने की ललक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिक्षकों की नियुक्ति से केवल बच्चों का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का उत्साह बढ़ा है। पालक मेलूराम जगत ने बताया कि उनकी बेटी तीसरी कक्षा में पढ़ रही है और अब शिक्षक नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं जिससे उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। इसी तरह श्री सुखसागर मरावी, श्री मनहरण दास मानिकपुरी और श्री मंगलिन नेताम ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और कहा कि खपराखोल जैसे छोटे और दूरस्थ गांव की चिंता कर शासन ने एक सराहनीय कार्य किया है। छात्राएं आंचल, कुमकुम और भूमिका ने भी बताया कि उन्हें पढ़ाई में अब बहुत मजा आ रहा है और शिक्षक उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। विद्यालय का परिवेश अब शिक्षण के अनुकूल हो चुका है और बच्चे पूरे मन से पढ़ाई में जुटे हुए हैं। खपराखोल की यह कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की प्रतीक बन गई है। यह साबित करती है कि जब शासन की मंशा साफ हो और नीति मजबूत हो, तो शिक्षा के अंधेरे कोनों में भी रौशनी पहुंचाई जा सकती है। युक्तियुक्तकरण की यह पहल अब सिर्फ स्कूल में शिक्षक लाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह गांवों में उम्मीद, आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य का आधार बन चुकी है।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत: विष्णुदेव साय

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली "बॉटर वुमन" के नाम से विख्यात शिप्रा पाठक ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने शिप्रा पाठक के पर्यावरण संरक्षण और विशेष रूप से सिंदूर पौधरोपण को जन-जन तक पहुंचाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने शिप्रा पाठक को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि शिप्रा पाठक ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किए गए कार्यों के लिए व्यापक स्तर पर पहचान प्राप्त की है। उनके नेतृत्व में पौधरोपण अभियान ने न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है, बल्कि आम लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित भी किया है।इस अवसर पर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रोफेसर हरिशंकर सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिप्रा पाठक के पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और ऐसे प्रयासों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

हेमंत खंडेलवाल बने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष: संगठन में सामंजस्य और गुटबाजी से निपटना बड़ी चुनौती

(पेज 1 का शेष)

गुटबाजी से निपटना प्राथमिकता

प्रदेश भाजपा में लंबे समय से क्षेत्रीय गुटबाजी हावी रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का गुट, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रभाव, संगठन के पुराने नेताओं का दबदबा और संघ से जुड़े नेताओं की अलग लॉबी- इन सभी के बीच संतुलन बनाना खंडेलवाल के कौशल की परीक्षा लेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर वे इस चुनौती को पार कर लेते हैं तो आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी को सीधा लाभ मिलेगा।

मोहन यादव का भरोसा, संकेत बड़े बदलाव के

मुख्यमंत्री मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल के बीच पुराने समय से ही अच्छे संबंध रहे हैं। सूत्रों की मानें तो खंडेलवाल की ताजपोशी के साथ ही प्रदेश भाजपा में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संगठनात्मक पदों पर नए चेहरों को मौका देना, कार्यकर्ता संवाद बढ़ाना और बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क खड़ा करना उनकी प्राथमिकता होगी।

भविष्य की रणनीति तय करेगी सफलता

प्रदेश भाजपा में अध्यक्ष पद केवल संगठन का नेतृत्व नहीं बल्कि सरकार और केंद्र के बीच सेतु की भूमिका भी निभाता है। हेमंत खंडेलवाल को अपनी टीम के चयन, कार्यकर्ताओं के सम्मान और विकास योजनाओं के प्रचार-प्रसार की रणनीति पर तुरंत काम शुरू करना होगा। आगामी नगर निगम और पंचायत चुनाव उनके नेतृत्व की पहली परीक्षा होंगे।

ओबीसी शासकीय सेवकों को पदोन्नति में मिलेगा आरक्षण

(पेज 1 का शेष)

कमलनाथ सरकार की पहल से बदली तस्वीर

कमलनाथ सरकार के फैसले से प्रदेश के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसर मिलेगा। कमलनाथ ने चुनावी घोषणा पत्र में ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसे प्राथमिकता दी।

भाजपा पर अदालत में मामला फंसाने का आरोप

विश्लेषकों के अनुसार कमलनाथ ने ओबीसी वर्ग को उनका हक दिलाने का फैसला किया था, लेकिन भाजपा ने कोर्ट में जाकर इसे रोक दिया। भाजपा का असली चेहरा अब सामने आ गया है। अदालत में सरकार के वकील लगातार तारीखें लेते रहे और ओबीसी छात्रों की भर्ती अटकती रही। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा हमेशा दोहरी रणनीति अपनाती रही है। एक ओर आरक्षण के समर्थन में बयान दिए जाते हैं, दूसरी ओर अदालती प्रक्रिया लंबी खिंचती जाती है।

पदोन्नति में आरक्षण पर भी असर

ओबीसी आरक्षण का प्रभाव सिर्फ शैक्षणिक और भर्ती प्रक्रिया पर ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर भी पड़ा है। मध्यप्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण लंबे समय से विवाद का विषय है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाई, उसके बाद ओबीसी कर्मचारियों को भी नुकसान हुआ। कमलनाथ सरकार ने इस पर अध्ययन समिति गठित कर आंकड़े इकट्ठा किए थे ताकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ठोस तर्क रखे जा सकें।

यह कांग्रेस और कमलनाथ की जीत

कांग्रेस नेताओं के अनुसार भाजपा ने ओबीसी वर्ग के हक छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह कांग्रेस और कमलनाथ की वैचारिक जीत है कि आज भाजपा को भी 27 फीसदी आरक्षण लागू करना पड़ रहा है। यह फैसला अदालत में पहले ही लागू हो जाता यदि भाजपा ने राजनीतिक अड़ंगे न लगाए होते। विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस इसे हमेशा अपनी उपलब्धि बताती रही जबकि भाजपा असहज स्थिति में रही। अब 2025 में पंचायतों और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी के बीच ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भाजपा सरकार ने यह कदम बढ़ाया है। प्रदेश में ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। करीब 52 फीसदी ओबीसी आबादी होने के कारण कोई भी दल इस वर्ग की उपेक्षा नहीं कर सकता। हाल के वर्षों में भाजपा की ओबीसी नेताओं को संगठन में ज्यादा जगह देने की रणनीति भी इसी का हिस्सा रही है।

लाखों ओबीसी युवाओं को भविष्य में मिलेगा लाभ

यदि कमलनाथ सरकार का कार्यकाल पूरा होता तो ओबीसी आरक्षण पर आज कोई विवाद ही नहीं होता। भाजपा अब इस फैसले को लागू करके श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओबीसी वर्ग को असली हक कांग्रेस ने ही दिलाया था। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि आरक्षण को लेकर भाजपा हमेशा प्रतिबद्ध रही है। अदालतों में मामला फंसा था, जैसे ही कानूनी अड़चनें दूर हुईं, सरकार ने फैसले पर मुहर लगा दी। ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे इस सियासी संग्राम में कांग्रेस ने जहां इसे अपनी वैचारिक जीत बताया, वहीं भाजपा सरकार ने इसे वर्ग के प्रति अपनी संवेदनशीलता कहा है। सच्चाई यह है कि लाखों ओबीसी युवाओं के लिए यह फैसला भविष्य निर्माण का अवसर लेकर आया है। अब देखना यह होगा कि कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया में यह कितना तेजी से लागू हो पाता है।

कमलनाथ का 18 माह का कार्यकाल में लिए अहम फैसले

कमलनाथ सरकार का कार्यकाल भले ही 18 माह का रहा हो लेकिन उसमें लिए गए कई निर्णय ऐतिहासिक रहे। किसानों की कर्जमाफी से लेकर कन्या विवाह योजना में अनुदान बढ़ाना, संबल योजना को फिर से शुरू करना, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज करना, गौशालाओं के लिए बजट जारी करना, युवाओं के लिए रोजगार मिशन शुरू करना, औद्योगिक निवेश को गति देना– इन सभी फैसलों का सीधा लाभ आम जनता को मिला। कमलनाथ सरकार ने 2019 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के निर्णय को मंत्रिपरिषद से पारित कर तुरंत लागू किया था। इस फैसले का प्रदेशभर में स्वागत हुआ लेकिन भाजपा के कई नेताओं ने इसे अदालत में चुनौती दी।

प्रकृति की गोद में सेहत से संवाद

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

पिछले सात दिन मैंने पुणे के पास स्थित प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में बिताए। यह अनुभव सिर्फ एक अवकाश नहीं था, बल्कि मेरे शरीर, मन और आत्मा के लिए एक गहन जागृति थी। पहाड़ी से घिरे इस शांत और हरे-भरे परिवेश ने मुझे तुरंत अपने भीतर की शांति से जोड़ दिया। मुनशी झील के किनारे, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आत्मांतन केंद्र की ताज़ी हवा और उच्च-ऊर्जा वाला वातावरण तनाव को तुरंत दूर कर देता है। एक सप्ताह बाद, मैं खुद के एक नए, अधिक ऊर्जावान और शांत स्वरूप को महसूस कर पा रहा हूँ। यह अनुभव किसी लग्जरी वेकेशन से बढ़कर, स्वास्थ्य के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता और आत्म-खोज का सफर था, जिसमें मैंने अपनी सेहत से संवाद किया।

प्राकृतिक चिकित्सा: शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर की जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं। तनाव, थकान, पाचन संबंधी समस्याएं और अनिद्रा जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। ऐसे में, प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) एक वरदान साबित होती है। यह कोई शौक या विलासिता नहीं, बल्कि "अंतर्मुखी जागरूकता की अनिवार्यता" है। यह पद्धति प्रकृति के पाँच तत्वों – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश – का उपयोग करके शरीर की स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता को जगाती है।

मेरे अनुभव में, प्राकृतिक चिकित्सा ने मुझे सिखाया

हाइड्रोथेरेपी (जल चिकित्सा): शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर ऊर्जा और ताजगी प्रदान करती है।

मिट्टी चिकित्सा: त्वचा और पाचन तंत्र को पुनर्जीवित करती है, शरीर को ठंडक पहुंचाती है।

सूर्य स्नान: प्राकृतिक रूप से विटामिन डी के स्तर को संतुलित करता है और मन को शांत करता है।

प्राणायाम और ध्यान: मानसिक स्पष्टता लाते हैं, तनाव कम करते हैं और श्वसन क्षमता में सुधार करते हैं।

आयुर्वेद और योग: प्राचीन ज्ञान का आधुनिक उपयोग प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, आयुर्वेद और योग ने मेरे अनुभव को और भी समृद्ध बनाया। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना हजारों साल पहले था।

आयुर्वेद: जीवन का विज्ञान

आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। इसने मुझे अपनी व्यक्तिगत प्रकृति (दोष- वात, पित्त, कफ) को समझने में मदद की। मुझे पता चला कि मेरी प्रकृति के अनुसार कौन-सा आहार और जीवनशैली मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। यह ज्ञान शरीर की जरूरतों को समझने और उसके अनुसार सही चुनाव करने में सहायक है।

योग: शारीरिक और मानसिक संतुलन का आधार

योग ने मेरे शरीर में अद्भुत लचीलापन और मानसिक एकाग्रता बढ़ाई। विभिन्न आसनों जैसे सूर्य नमस्कार ने पूरे शरीर को सक्रिय किया, जबकि शवासन ने गहन विश्राम प्रदान किया। प्राणायाम (श्वास-नियंत्रण) ने मेरे फेफड़ों को मजबूत किया और मन को शांत किया, जिससे विचारों में स्पष्टता आई। प्रकृति के हरे-भरे वातावरण में योग का अभ्यास करना किसी ध्यान से कम नहीं था, जिसने मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाया।

स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति: घर पर करें शुरुआत, केंद्र पर करें विस्तार

मेरा यह अनुभव एक स्पष्ट संदेश देता है: स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, और यह कोई शौक नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं, जीवन की कोई भी उपलब्धि हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के सभी उपाय दिए हैं– हमें बस उन्हें अपनाने की आवश्यकता है।

आपके लिए एक्शन प्लान: घर पर कैसे करें शुरुआत?

सुबह की दिनचर्या में बदलाव

जल्दी उठें: प्रतिदिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें।

गुनगुना पानी: सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पिएं, यह शरीर की सफाई में मदद करता है।

हल्का व्यायाम: रोजाना 15-30 मिनट योग, प्राणायाम या तेज सैर करें।

धूप स्नान: रोजाना 10-15 मिनट सुबह की हल्की धूप लें, यह विटामिन डी के लिए आवश्यक है।

चबा-चबा कर खाएं: भोजन को धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। रात का भोजन सूर्यास्त से पहले या सोने से 2-3 घंटे पहले करें।

प्राकृतिक भोजन: बाजार के खाद्य पदार्थों, अतिरिक्त चीनी और जंक फूड से बचें। ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज को प्राथमिकता दें।

ध्यान/प्राणायाम: रोजाना 10-15 मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें।

प्रकृति से जुड़ें: आस-पास के पार्कों या हरियाली वाली जगह पर समय बिताएं।

यदि संभव हो, तो साल में एक बार 10-15 दिनों के लिए गहन आयुर्वेदिक पंचकर्म या नेचुरोपैथी कार्यक्रम में भाग लें। यह शरीर की गहरी सफाई और पुनर्वास के लिए अत्यंत प्रभावी होता है।

स्वयं से जुड़िए, स्वस्थ रहिए

यह अनुभव मेरी तरफ से एक हार्दिक और अनुभव-सिद्ध सलाह है। हम अक्सर धन, पद और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे तो ये सब व्यर्थ हैं। मेरा मानना है कि "प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना ही सच्ची स्वस्थ जीवनशैली है।" आज ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का निर्णय लें। छोटी शुरुआत करें, लेकिन निरंतर बने रहें। प्रकृति आपको अवश्य पुरस्कृत करेगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अपने शरीर से संवाद कीजिए, उसकी भाषा को समझिए, और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए।

भ्रष्टाचार एवं अत्यवस्था की पोल न खुल जाये इसलिए भाजपा नेताओं और प्रशासन ने प्रभारी मंत्री को नहीं आने दिया टिमरनी

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह, टिमरनी। जिले के प्रभारी मंत्री श्री विश्वास सारंग हरदा जिले के दौरे पर थे। तय कार्यक्रम के अनुसार मंत्री को टिमरनी होकर हरदा जाना था किन्तु भाजपा नेताओं एवं प्रशासन ने उन्हें छिंदगांव से टेमागाव रोड़ पर फोरलेन से सोडलपुर होते हुए हरदा पहुंचा दिया। जिसकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने निंदा करते हुए अपना विरोध जताया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने बताया कि टिमरनी नगर में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते व्यापारी एवं आम नागरिक बहुत परेशान है। न तो ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित सर्विस रोड बनाया गया है एवं प्रशासन ने आवागमन हेतु जो बायपास रोड उपलब्ध कराया है वह भी कच्चा है, जिससे वाहन चालकों को एवं आम नागरिकों को परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन वाहन फंस रहे हैं। लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। यदि प्रभारी मंत्री टिमरनी से होकर जाते तो उन्हें भी इसी मार्ग से गुजरना पड़ता जिससे प्रशासन एवं स्थानीय भाजपा नेताओं की किरकिरी होती एवं उनके विकास के दावों की पोल खुलती, इसलिए प्रशासन ने मंत्री का रास्ता ही बदल दिया। जायसवाल ने आरोप लगाते हुआ बताया कि जिस तरह से टिमरनी में ब्रिज निर्माण के चलते आम नागरिक परेशान है।

नतीजा एक न एक दिन जरूर निकलेगा, पढाई करते रहो, इम्तिहान देते रहोः अशोक मिजाज

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह, सागर। पं. दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में दीक्षारंभ कार्यक्रम के अंतिम दिन नवागत विद्यार्थियों को क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देने पर पुरस्कृत किया गया। मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की अभिनव पहल के अंतर्गत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सरोज गुप्ता के मार्गदर्शन में तीन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

दीक्षारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार एवं शायर अशोक मिजाज ने विद्यार्थियों को संबोधित करते कहा कि विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में मिले समय का उपयोग भविष्य को गढ़ने में करना चाहिए। आपने कहा कि ख्यालों व ख्वाबों को ऊंची उड़ान देते रहो, पर अपने परों की ताकत पर भी ध्यान देते रहो, नतीजा एक न एक दिन अवश्य निकलेगा। पढ़ाई करते रहो इम्तिहान देते रहो। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हुए उनको आलस्य न करने की सलाह दी। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आकाशवाणी उदघोषिका साहिबा नासिर खान ने कहा कि आगे आने वाले 5 वर्ष आपके जीवन को तय करेंगे कि आप अपने भविष्य को कहां ले जाना चाहते हैं। उन्होंने उन्नति फाउंडेशन के माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण के विषय में भी विद्यार्थियों को परिचित कराया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सरोज गुप्ता ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जीवन की सफलता चरेवेति चरैवेति के आधार पर ही निर्धारित होता है अर्थात आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है।

जीवन का ठहराव विकास को अवरुद्ध करता है और हमेशा आगे बढ़ाने की ललक हम सभी को उन्नति प्रदान करती है। दीक्षारंभ कार्यक्रम का उद्देश्य ही यह है कि आप सभी अपने गुरु से आज दीक्षित हो गए हैं। कार्यक्रम के संबंध में डॉ. संदीप सबलोक ने बताया कि इस दौरान डॉ. संतोष सेन ने पुस्तकालय, डॉ. जयनारायण यादव व कीर्ति रैकवार ने एनसीसी, डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय सेवा योजना आदि के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी दी। साथ ही डॉ. सुनील साहू ने विद्यार्थियों के साथ संपूर्ण महाविद्यालय के विभागों का भ्रमण किया।कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम प्रभारी डॉ. अमर कुमार जैन एवं क्विज प्रतियोगिता का संचालन डॉ. शुचिता अग्रवाल द्वारा किया गया।

गणना प्रपत्रों को ऑनलाइन भरना 'डिजिटल इंडिया' पहल का एक प्रमुख पहलू हैः सैयद शहजाद अहमद

-अमित राय

जगत प्रवाह, बक्सर। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 अभियान के तहत गणना पपत्रों को ऑनलाइन भरना आरम्भ हो गया है। गणना फार्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के अवसर पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह राजस्व एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता, डुमराँव, सैयद शहजाद अहमद ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय जनगणना में गणना प्रपत्रों को ऑनलाइन भरना "डिजिटल इंडिया" पहल का एक प्रमुख पहलू है, जो डिजिटल समावेशन और दक्षता को बढ़ावा देता है। नागरिक सीधे पोर्टल के माध्यम से अपना डेटा दर्ज कर सकते हैं। साथ ही जनगणना अधिकारियों द्वारा पारंपरिक व्यक्तिगत गणना भी कर सकते हैं। अहमद ने आगे कहा कि डिजिटल तरीकों की ओर इस बदलाव का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, कागज-आधारित फॉर्म पर निर्भरता कम करना और डेटा संग्रह और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। ऑनलाइन गणना प्रपत्र कई लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें बढ़ी हुई दक्षता, कम लागत और बेहतर डेटा सटीकता शामिल है। ये डेटा संग्रह को सुव्यवस्थित करते हैं, जिससे जानकारी एकत्र करना तेज और आसान हो जाता है, और ये मैन्युअल डेटा प्रविष्टि से जुड़ी त्रुटियों को कम करते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन फॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाते हैं, अधिक पहुँच प्रदान करते हैं, और आसान डेटा विश्लेषण और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि 25 जून से 3 जुलाई 2025 तक, राज्य के लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र छपवाकर वितरित किए जा रहे हैं। यह प्रपत्र 23 जून 2025 तक के मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर आंशिक रूप से भरे हुए हैं, जिन्हें 77,895 बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 20,603 और बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है। ये बीएलओ 24 जून 2025 तक मतदाता सूची में दर्ज सभी 7.90 करोड़ मतदाताओं को घर-घर जाकर प्रपत्र दे रहे हैं। इसके अलावा ये प्रपत्र ईसीआई के पोर्टल से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 50 प्रमाणित प्रपत्र जमा कर सकते हैं। गणना प्रपत्रों को भरकर 25 जुलाई 2025 से पहले जमा करना होगा। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु बीएलओ के साथ-साथ स्वयंसेवकों को भी तैनाती की गई है। लगभग 4 लाख स्वयंसेवक– जिनमें सरकारी कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस आदि शामिल हैं – मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध हैं। इनका उद्देश्य वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, निर्धन और अन्य वंचित वर्गों की सहायता करना है।

सम्पादकीय

विश्व राजनीति में उथल-पुथल, कारण, परिणाम और भविष्य

वर्तमान समय में विश्व राजनीति एक बार फिर से बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जिस 'एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था' की कल्पना की गई थी, वह अब बहुध्रुवीय होती जा रही है। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ जैसी महाशक्तियां अपनी शक्ति के नए समीकरण बना रही हैं। कई क्षेत्रीय शक्तियां भी उभर कर वैश्विक मंच पर अपने हितों को मुखर कर रही हैं। इसी शक्ति संघर्ष ने दुनिया के कई हिस्सों को राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और संघर्ष की आग में झोंक दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध है जिसने यूरोप की स्थिरता को सीधा चुनौती दी है। 2022 में शुरू हुए इस युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ऊर्जा संकट, अनाज संकट और शरणार्थी समस्या ने कई देशों के आंतरिक राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। अमेरिका और नाटो का सीधा हस्तक्षेप, रूस की जिद और यूक्रेन का प्रतिरोध इस संघर्ष को लंबे समय तक खींच रहा है। एशिया में चीन लगातार आक्रामक रवैया अपना रहा है। दक्षिण चीन सागर में उसका वर्चस्व बढ़ाना, ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से टकराव, भारत के साथ सीमा विवाद और बेल्ट एंड रोड परियोजना के माध्यम से छोटे देशों को ऋणजाल में फंसाना- ये सभी उसकी विस्तारवादी नीतियों के प्रमाण हैं। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक नई शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश क्वाड के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य पूर्व की राजनीति भी अशांत है। इजराइल और हमास के बीच हालिया युद्ध ने दुनिया को फिर से यह याद दिला दिया कि यह क्षेत्र स्थायी शांति से कोसों दूर है। ईरान और सऊदी अरब के बीच सत्ता संतुलन, सीरिया और यमन के गृहयुद्ध, आतंकवाद और धर्म के आधार पर फैलाई जा रही कट्टरता ने इस क्षेत्र को संवेदनशील बनाए रखा है। हाल ही में अमेरिका द्वारा इराक और सीरिया में की गई सैन्य कार्रवाइयों और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी देशों की चिंता, इस इलाके में उथल-पुथल को और जटिल बना रही हैं।

यूरोप में भी उथल-पुथल जारी है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन आंतरिक असंतोष, आर्थिक दबाव और अलगाववादी प्रवृत्तियों से जूझ रहा है। फ्रांस और जर्मनी में दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, जिससे यूरोपीय एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बेलारूस, पोलैंड और बाल्टिक देशों में रूस के प्रभाव को रोकने के लिए नाटो अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ा रहा है। अमेरिका में भी घरेलू राजनीति में तीव्र ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। ट्रंप और बाइडेन के समर्थकों के बीच वैचारिक टकराव लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है। आंतरिक नस्लीय और सामाजिक विभाजन भी अमेरिकी राजनीति को अस्थिर बना रहे हैं। इन सारी घटनाओं का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों पर पड़ रहा है। ऊर्जा संकट, खाद्यान्न संकट, महंगाई, बेरोजगारी और प्रवासियों की समस्या ने दुनिया के कई देशों में जनता को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते सत्ता परिवर्तन इसका उदाहरण है। इन चुनौतियों के बीच कुछ सकारात्मक प्रयास भी हो रहे हैं। जैसे, ब्रिक्स समूह का विस्तार, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देशों के बीच नई साझेदारियां। लेकिन ये प्रयास अभी अस्थिर राजनीति और भू-राजनीतिक टकरावों से दब जाते हैं। आने वाले समय में विश्व को स्थिर बनाने के लिए महाशक्तियों को संवाद के रास्ते खोजने होंगे। छोटे देशों को अपनी आंतरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना होगा।

सियासी गहमागहमी

अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए नित नए प्रयास करती बघेल एंड कंपनी

कभी छत्तीसगढ़ की राजनीति में 'आधुनिक कृषक राजा' का तमगा पाने वाले भूपेश बघेल इन दिनों हथकड़ी के डिजाइन पर रिसर्च करते नजर आ रहे हैं। खबरें हैं कि उनकी 'चंडाल चौकड़ी' यानी वे चार-पांच अनन्य सहयोगी, जिन्होंने खनन से लेकर तबादलों तक का गंगाजल खुद ही छलका दिया। राजनीति में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं, लेकिन यहां तो भ्रष्टाचार भी शर्मिंदा होकर पूछ रहा है- "भाई, थोड़ा मुझे भी हिस्सा दे दो, अकेले ही क्यों खा रहे हो?" अब जांच एजेंसियां भी सोच में पड़ गई हैं कि पहले किसे पकड़ा जाए- बघेल जी को, उनकी चौकड़ी को या उन कमीशनखोर फाइलों को, जिनके पन्ने पैसे की महक से महकते रहे। चौकड़ी के एक सदस्य ने तो गुपचुप कानाफूसी में कहा अगर हथकड़ी बंधी तो क्या, पब्लिसिटी तो मिल ही जाएगी। वैसे भूपेश बघेल की यह चौकड़ी कभी उनके लिए 'चाणक्य मंडल' मानी जाती थी। योजनाओं की मलाई से लेकर अधिकारियों के तबादलों की मलाईदार लिस्ट तक सब इनके माध्यम से ही तय होता था। लेकिन अब वही मंडल 'हथकड़ी मंडल' बनने को तैयार खड़ा है।

सभी मंदिर में मत्था रगड़ने वाले नेताजी को सांत्वना दे रहे हैं

मध्यप्रदेश भाजपा में हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई नेताओं के सपने अधूरे रह गये। मध्यप्रदेश के कई नेताजी इन दिनों रात को सोते हुए करवट बदलते-बदलते प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे थे। पर बेचारे क्या करें, सभी का सपना चूर-चूर हो गया है। एक नेताजी तो इस कुर्सी के इंतजार में इतने दुबले हो गए कि लोग उन्हें देखकर कहने लगे- अरे नेताजी, अध्यक्ष नहीं बन पाए तो क्या हुआ, वजन तो कम हो गया। वहीं, दूसरे नेता जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए भगवान के दरबार से लेकर दिल्ली दरबार तक माथा रगड़ दिया, लेकिन कुर्सी भी ठहरी, बड़ी बेवफा। हर बार किसी और के सिर सजा दी जाती है। कुछ नेताओं ने तो नया जुमला ही बना लिया है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी प्रेमिका की तरह होती है, जिससे सबको प्यार होता है लेकिन किसे मिल जाए

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है - भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को "भारत की क्राइम कैपिटल" बना दिया है।

आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध राज्य 'नया नॉर्मल' बन चुका है - और सरकार पूरी तरह नाकाम।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश में कुपोषण एक विकराल समस्या बनता जा रहा है। प्रदेश के 55 जिलों में से 45 जिलों के बच्चों में कम वजन के मामले रेड जोन में पाए गए हैं। प्रदेश में कुपोषण से लड़ने के लिए 4895 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है लेकिन प्रदेश की 97000 आंगनबाड़ियों में 38% बच्चे कुपोषण की चपेट में पाए गए।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

मध्यप्रदेश की राजनीति में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज है पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का नाम

समता पाठक/जगत प्रवाह

पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का नाम भारतीय राजनीति, विशेषकर मध्यप्रदेश की राजनीति के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वे न केवल एक कुशल प्रशासक थे बल्कि संघ विचारधारा से जुड़े ऐसे नेता भी, जिन्होंने गांव, किसान और ग्रामीण विकास को अपनी राजनीति का आधार बनाया। उनका जन्म 11 नवंबर 1924 को मध्यप्रदेश के निमाड़ अंचल के कुक्षी तहसील के कड़ी गांव में हुआ था। उनका परिवार मूलतः कृषक था और इस पृष्ठभूमि ने उनके राजनीतिक विचारों को बहुत प्रभावित किया। पटवा जी ने अपनी शिक्षा प्रारंभिक स्तर तक ही प्राप्त की और युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गये। संघ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति को अपने जीवन का मूलमंत्र बनाया। 1951 में जब भारतीय जनसंघ का गठन हुआ, तब पटवा जी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वे 1957 में पहली बार विधायक बने और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जनसंघ के संस्थापक नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाया।

पटवा जी की नेतृत्व क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब 20 जनवरी 1980 को उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि केंद्र में इंदिरा गांधी की सत्ता वापसी के बाद कुछ ही दिनों में उनकी सरकार भंग कर दी गई, परंतु इतने छोटे कार्यकाल में भी उन्होंने प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया। इसके बाद 5 मार्च 1990 को वे पुनः मुख्यमंत्री बने। उनका यह कार्यकाल लगभग दो वर्ष का रहा, जिसमें उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रशासन में व्यापक सुधार किये। किसानों की कर्जमाफी, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, नर्मदा जल के उपयोग की दिशा में नीतियां बनाना और औद्योगिकीकरण को गति देना उनके मुख्य कार्य रहे।

सुंदरलाल पटवा की छवि एक सादगीपूर्ण, ईमानदार और अनुशासित नेता की थी। वे सत्ता का प्रदर्शन करने में नहीं, बल्कि समस्याओं के समाधान में विश्वास रखते थे। उनका लहजा सदा ठेठ मालवी रहता, जिससे आमजन स्वयं को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों में कड़े निर्णय लिये। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1997 में भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब केन्द्र में सरकार बनी, तब सुंदरलाल पटवा को केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया। वे ग्रामीण विकास मंत्री रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना को आकार देने में उनकी भूमिका मानी जाती है। पटवा जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी हार नहीं मानी। उम्र के अंतिम पड़ाव तक वे सक्रिय रहे। 1999 में उन्होंने छिंदवाड़ा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ा। हालांकि वे हार गये परंतु भाजपा ने उन्हें एक जुझारू नेता के रूप में देखा। उनका जीवन बेहद सादा था। वे भव्यता या प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते थे। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का उपयोग उन्होंने सामान्य कार्यस्थल के रूप में किया। वे स्वयं भोजन बनाना जानते थे और सरलता से कार्यकर्ताओं के बीच बैठ जाते थे। संघ से आये अनुशासन और विचारधारा को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। यही कारण था कि पार्टी के भीतर उनका सम्मान निर्विवाद रहा। सुंदरलाल पटवा को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश में भाजपा को खड़ा करने में उनकी भूमिका सर्वाधिक मानी जाती है। उनके जीवन का अंतिम काल भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में ही बीता। 28 दिसंबर 2016 को उनका निधन हो गया। वे गांव, गरीब और किसान के सच्चे हितैषी थे। पटवा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि विचारधारा के प्रति निष्ठा, सरलता, ईमानदारी और कठोर परिश्रम ही किसी भी व्यक्ति को महान बनाते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा अपने आप में उदाहरण है कि कैसे एक सामान्य परिवार का युवक, संगठन और जनता के विश्वास से प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बनता है। आज भी भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। वे ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कभी पद को स्वयं का गौरव नहीं माना, बल्कि पद के कर्तव्यों को सर्वोच्च रखा। उनके द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं का लाभ मध्यप्रदेश की जनता आज भी उठा रही है।

उर्वरक नीति में बदलाव अब समय की मांग

-विजय गर्ग

हरित क्रांति के दौर से पहले किसान प्राकृतिक खेती किया करते थे, जिसमें रासायनिक उर्वरकों की खपत नगण्य थी। उस समय फसलों का उत्पादन और उत्पादकता कम थी। देश के बार-बार अकालग्रस्त होने से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विदेशी अनाज के आयात पर निर्भर थी। वर्ष 1943 के बंगाल अकाल में 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मारे गए। ऐसी विकट परिस्थितियों में, नीतिकारों ने हरित क्रान्ति के जनक डा. नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित गेहूं की बौनी किस्मों और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से धान की बौनी किस्मों का आयात करके, देश में हरित क्रांति का आगाज किया। इन उन्नत गेहूं-धान की बौनी किस्मों और बाजरा-ज्वार की हाईब्रीड किस्मों से पूरा उत्पादन लेने के लिए, भारी मात्रा में उर्वरकों का आयात और उत्पादन व भूजल आधारित ट्यूबवेल से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। हरित क्रांति दौर में अपनाए गए कृषि सुधारों से देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में कई गुणा बढ़ोतरी हुई। जिसकी बदौलत पिछले 5 दशकों से, लगातार बढ़ती आबादी के बावजूद, देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना हुआ है। चावल का पचास हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का वार्षिक निर्यात भी कर रहा है।

भारत में वर्ष 2022 में उर्वरक की औसत खपत 193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी और लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन उर्वरक की खपत हुई। भारत में यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उर्वरक है। देश में उर्वरक की खपत प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। उर्वरकों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सरकार भारी मात्रा मे वार्षिक आयात करती है। हरियाणा-पंजाब-पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में गेहूं-धान फसल चक्र की उत्पादकता 10 टन वार्षिक से ज्यादा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि प्रदेशों में भी वार्षिक धान की 2-3 फसल चक्र की उत्पादकता 10 टन से ज्यादा है। इसलिए इन प्रदेशों में उर्वरक की वार्षिक खपत राष्ट्रीय औसत से दुगने से भी ज्यादा प्रति हेक्टेयर 250 किलो नाइट्रोजन, 120 किलो फास्फोरस और 200 किलो पोटेशियम के आसपास है। जबकि वर्षा आधारित बारानी फसलों बाजरा, ज्वार, दलहन, तिलहन आदि के उत्पादक राज्यों में उर्वरक की वार्षिक खपत राष्ट्रीय औसत से काफी कम रहती है। उच्च उत्पादकता वाली कन्दमूल और गन्ने जैसी फसलों को अच्छी पैदावार देने के लिए ज्यादा

> कृषि ग्रेड उर्वरक किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक नहीं मिलने के चलते सरकार द्वारा नियंत्रित सहकारी उर्वरक कम्पनी इफ्को किसानों को वर्ष 2021 से नैनो यूरिया बेच रही है। इफ्को कम्पनी के दावों के अनुसार नैनो यूरिया तरल स्वरूप में, पारंपरिक दानेदार यूरिया की 50 किलो की एक बोरी का विकल्प है। हरित क्रांति दौर से अग्रणी रहे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय आदि अनेक संस्थानों के अनुसंधान में नैनो यूरिया को कृषि क्षेत्र के लिए अनुपयोगी पाया गया है।

पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे इन फसलों की रासायनिक उर्वरक की खपत बहुत ज्यादा होती है।

हरित क्रांति दौर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, नीतिकारों ने कृषि क्षेत्र के लिए रासायनिक उर्वरक की सस्ती दर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक सब्सिडी नीति को अपनाया। किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने पर सरकार का व्यय पिछले वित्त वर्ष में 6 प्रतिशत घटकर रुपये 1,77,129.5 करोड़ रह गया, जो 2023-24 के दौरान रुपये 1,88,291.62 करोड़ था। यह गिरावट मुख्य रूप से यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के आयात में गिरावट तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी के कारण हुई है। गिरावट के बावजूद, वास्तविक सब्सिडी बजट में प्रदान की गई रुपये 1,71,310 करोड़ से 3.4 प्रतिशत अधिक है। यूरिया, जो एक पूर्णतः नियंत्रित उर्वरक है, का विक्रय मूल्य पिछले कई वर्षों से 267 रुपये प्रति (45 किग्रा) बैग पर बना हुआ है। उद्योग के अनुमानों से पता चलता है कि सब्सिडी के बिना यह लगभग 1,750 रुपये प्रति बैग हो सकता है। इसी प्रकार, डीएपी का खुदरा मूल्य 1,350 रुपये प्रति बैग तय किया गया है, जो बिना सब्सिडी के लगभग 3,500 रुपये प्रति बैग हो जाएगा।

सरकारी विभागों के कदाचार की वजह से लगभग आधे से ज्यादा सब्सिडी वाले कृषि ग्रेड उर्वरक की खपत उद्योगपतियों की फैक्टरियों में गैर-कानूनी तौर पर हो रही है यानी कृषि के लिए दी जा रही केन्द्रीय उर्वरक सब्सिडी का लाभ किसानों को नहीं मिलकर, उद्योगपतियों को मिल रहा है। हर वर्ष फसल बुआई के समय किसानों को उर्वरक पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। उन्हें उर्वरक खुले बाजार से महंगे दाम पर ब्लैक में लेना पड़ रहा है। किसानों को समय पर पूरी मात्रा में उर्वरक नहीं मिल पाने से, फसल की उत्पादकता पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

कृषि ग्रेड उर्वरक किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक नहीं मिलने के चलते सरकार द्वारा नियंत्रित सहकारी उर्वरक कम्पनी इफ्को किसानों को वर्ष 2021 से नैनो यूरिया बेच रही है। इफ्को कम्पनी के दावों के अनुसार नैनो यूरिया तरल स्वरूप में, पारंपरिक दानेदार यूरिया की 50 किलो की एक बोरी का विकल्प है। हरित क्रांति दौर से अग्रणी रहे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय आदि अनेक संस्थानों के अनुसंधान में नैनो यूरिया को कृषि क्षेत्र के लिए अनुपयोगी पाया गया है। कृषि ग्रेड उर्वरक के उद्योग में गैर-कानूनी दुरुपयोग को रोकने और उर्वरक सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाकर किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। कृषि सुधारों में सबसे ज्यादा तर्कसंगत उपाय उर्वरक सब्सिडी का किसानों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण रहेगा। उर्वरक सब्सिडी के मौजूदा सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रति एकड़ सिंचित भूमि के लिए 7,000 रुपये और वर्षा आधारित बारानी भूमि के लिए 4,000 रुपये दिये जाने चाहिए। कृषि मंत्रालय ने पहले ही पीएम-किसान, पीएम फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी विभिन्न योजनाओं के आंकड़े तथा प्रत्येक किसान को नवीनतम विशिष्ट आईडी, जिसमें भूमि जोत, बोई गई फसल और उपज जैसे विवरण शामिल हैं, उर्वरक मंत्रालय के साथ साझा कर दिया है। उर्वरक सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के रूप में किये जाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे, जिससे योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार होता है। इसका मुख्य लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना है।

मानसून में मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लिए चुनौती और तैयारी

-विजया पाठक

भारत में मानसून केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, कृषि, अर्थव्यवस्था और शासन-प्रशासन के लिए परीक्षा की घड़ी होती है। यह वर्षा ऋतु एक ओर हरियाली, फसलों की सुरक्षा और जलाशयों के भरने का प्रतीक है तो दूसरी ओर बाढ़, जलभराव, बीमारियां और आपदा प्रबंधन की बड़ी चुनौती भी। विशेषकर मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और बंगाल जैसे राज्यों के लिए मानसून हर वर्ष प्रशासनिक तैयारियों की वास्तविक परीक्षा बनकर आता है। मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल बड़ा है और यहां नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन जैसी कई नदियां बहती हैं। मानसून के दौरान इन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में होने वाली अतिवृष्टि से सड़क संपर्क टूटना, पुल-पुलियों को क्षति पहुंचना और गांवों का मुख्यधारा से कट जाना आम बात है। इसलिए हर साल अप्रैल-मई से ही राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन के व्यापक इंतजाम शुरू करने होते हैं।

वर्ष 2024 के अनुभवों से सरकार ने सीखा कि जलभराव से होने वाली क्षति केवल बाढ़ प्रभावित जिलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी नालों के उफान, सीवेज ओवरफ्लो और संक्रमणजन्य रोगों के फैलाव का खतरा पैदा करती है। इसके लिए नगर निगमों को मानसून पूर्व नालों की सफाई के आदेश दिए गए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा जैसे बड़े शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गये, ताकि जल निकासी बाधित न हो।

राज्य सरकार के उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

मध्यप्रदेश सरकार ने मानसून से पहले राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को सक्रिय किया। आपदा प्रबंधन विभाग, नगर निगम, पुलिस, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग के बीच समन्वय स्थापित किया गया। हर जिले में कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई कि वे संवेदनशील गांवों की सूची तैयार करें। नर्मदा और अन्य प्रमुख नदियों के तटवर्ती गांवों में चेतावनी तंत्र मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्य सरकार ने राहत शिविरों की व्यवस्था, पशुधन के लिए अलग शेड, चारा भंडारण, आवश्यक दवाइयों का स्टॉक और नाव-बोट की उपलब्धता भी सुनिश्चित की। SDRF और NDRF की तैनाती, बाढ़ बचाव दलों का प्रशिक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्थलों का चिह्नीकरण मानसून पूर्व तैयारी का हिस्सा रहा।

भूस्खलन और बादल फटने का खतरा

उत्तराखंड के लिए मानसून का अर्थ केवल बारिश नहीं, बल्कि भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं का डर भी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री जैसे चारधाम यात्रा मार्ग पर वर्षा के दौरान लगातार भूस्खलन होते हैं। इससे तीर्थयात्रियों की जान जोखिम में पड़ती है और आपदा प्रबंधन को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार को मई से ही सड़क चौड़ीकरण, पहाड़ियों की स्टोन नेटिंग, भूस्खलन रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल और आपातकालीन मार्गों की मरम्मत जैसे कार्यों को प्राथमिकता देनी होती है।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली: शहरी बाढ़ की समस्या

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और दिल्ली जैसे महानगरों में मानसून के समय शहरी बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरना, नालों का ओवरफ्लो, ट्रैफिक जाम और बिजली आपूर्ति बाधित होना आम दृश्य बन गया है। एनसीआर में गुरुग्राम और नोएडा की हाईराइज सोसाइटीज भी जलभराव से अछूती नहीं रहतीं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ना और निचले इलाकों में बाढ़ आना प्रशासन के लिए हर साल चुनौती बनता है। वर्ष 2023 और 2024 में यमुना के जलस्तर ने रिकॉर्ड तोड़ा, जिससे ITO, राजघाट, यमुनाबाजार जैसे इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया था। दिल्ली सरकार मानसून पूर्व कंजरवेंसी स्टाफ को सक्रिय कर नालों की सफाई कराती है, परंतु बढ़ती आबादी और अनियोजित विकास के कारण यह समस्या विकराल होती जा रही है।

पश्चिम बंगाल: बाढ़ और चक्रवात की दोहरी मार

बंगाल में मानसून का आगमन बाढ़ और चक्रवात, दोनों का संकेत होता है। सुंदरबन क्षेत्र, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हुगली और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में भारी वर्षा से गांव कट जाते हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटबंध टूटना आम बात है। अम्फान, यास, बुलबुल जैसे चक्रवातों ने यहां मानसून से पहले ही तबाही मचाई। इसलिए बंगाल सरकार मानसून से पूर्व तटबंधों की मरम्मत, राहत शिविरों की व्यवस्था, सामुदायिक किचन और चेतावनी तंत्र को सक्रिय कर देती है।

दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता

भारत को मानसून आपदाओं को रिलीफ बेस्ड मैनेजमेंट के बजाय रिस्क रिडक्शन बेस्ड मैनेजमेंट की ओर ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए नदियों की ड्रेजिंग और कैचमेंट एरिया ट्री प्लांटेशन। शहरी नियोजन में जलनिकासी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। आपदा प्रबंधन को स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। बाढ़ पूर्व चेतावनी तंत्र को एआई और रडार आधारित तकनीक से जोड़ना। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ स्थानीय स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर मानसून भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, परंतु यही मानसून उचित प्रबंधन के अभाव में आपदा बन जाता है। मध्यप्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों को चाहिए कि वे मानसून को केवल मौसम नहीं बल्कि 'आपदा प्रबंधन और विकास नीति का केन्द्रीय तत्व' मानें। तभी हम आने वाले वर्षों में जलभराव, बाढ़ और मानसूनजनित बीमारियों से होने वाले नुकसान को कम कर सकेंगे। मानसून के साथ जीना भारतीय जीवन पद्धति का हिस्सा है, इसे प्राकृतिक आपदा से प्राकृतिक पूंजी बनाने के लिए सतत, वैज्ञानिक और सहभागी दृष्टिकोण ही एकमात्र विकल्प है।

कहीं डोनाल्ड ट्रंप भारत, इजराइल और यूक्रेन के बीच षडयंत्र तो नहीं रच रहे

-विजया पाठक

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति प्रदर्शन अक्सर देशों की प्रतिष्ठा, सुरक्षा और रणनीतिक हितों के केंद्र में रहता है। लेकिन क्या वाकई एक देश को शक्तिशाली साबित करने का एकमात्र तरीका युद्ध, सैन्य प्रदर्शन और टकराव की नीति है? रूस-यूक्रेन, इजराइल-ईरान, भारत-पाकिस्तान जैसे मौजूदा टकराव न केवल इस सवाल को उठाते हैं, बल्कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका की भूमिका, विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की मंशा पर भी सवाल खड़े करते हैं। शक्ति प्रदर्शन का अर्थ केवल युद्ध नहीं है। यह किसी देश की सैन्य, आर्थिक, तकनीकी और वैचारिक शक्ति का ऐसा प्रदर्शन है जिससे वह अन्य देशों को प्रभावित या नियंत्रित कर सके। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, अमेरिका अपने सैन्य अड्डों और डॉलर की ताकत के जरिए, जबकि भारत डिजिटल डिप्लोमेसी व सॉफ्ट पॉवर के जरिए यह काम करता है। लेकिन कई बार यह शक्ति प्रदर्शन सैन्य टकराव में बदल जाता है- जैसे रूस-यूक्रेन, इजराइल-ईरान, और भारत-पाकिस्तान के मामलों में देखा जा सकता है।

विस्तारवाद बनाम अस्तित्व की लड़ाई

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तीन वर्ष पहले 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ। इस युद्ध का कारण था भू-राजनीतिकरण। यूक्रेन पश्चिमी देशों, विशेषकर नाटो और यूरोपीय संघ के करीब जाना रूस को असहज करता रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को "ऐतिहासिक रूस" का हिस्सा बताया और नाटो विस्तार को रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। यही नहीं क्रीमिया और डोनबास को लेकर विवाद गहराया। दरअसल वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के अधिग्रहण और डोनबास क्षेत्र में रूसी-समर्थक विद्रोहियों का समर्थन इस युद्ध का पूर्व संकेत था। कुल मिलाकर अब तक लाखों लोगों का विस्थापन, वैश्विक ऊर्जा संकट, खाद्यान्न आपूर्ति में बाधा, यूरोप में अस्थिरता और अमेरिका-रूस टकराव जैसी स्थिति बनती जा रही है।

अस्तित्व की चिंता या वर्चस्व की लड़ाई

इजराइल और ईरान के बीच चल रहा विवाद दशकों पुराना है लेकिन 2020 के बाद से विशेष रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजराइल के सीरिया व गाजा में हमलों के चलते यह टकराव और बढ़ गया। इसका सबसे बड़ा कारण है धार्मिक और राजनीतिक वैमनस्य- शिया ईरान और यहूदी इजराइल के बीच वैचारिक टकराव। इजराइल को डर है कि यदि ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है, तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। सीरिया, लेबनान (हिजबुल्लाह), गाजा (हमास) और यमन जैसे मोर्चों पर दोनों देश लगातार एक-दूसरे के खिलाफ सक्रिय हैं।

ऐतिहासिक घाव और कश्मीर का प्रश्न

भारत-पाकिस्तान के बीच पिछले 07 दशकों से विवाद गहराया हुआ है। वर्ष 1947 के विभाजन के बाद से ही कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। अब तक तीन पूर्ण युद्ध (1947, 1965, 1971) और कारगिल संघर्ष (1999) इसका प्रमाण हैं। अब तक भारत-पाक के बीच में कश्मीर का विषय, सीमा पार आतंकवाद, पानी के बंटवारे जैसे मुद्दे (सिंधु जल संधि), पुलवामा (2019) और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा किये। वर्तमान स्थिति देखी जाये तो भारत ने अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर को पूर्ण रूप से अपना अंग घोषित किया, जिससे पाकिस्तान ने विरोध जताया। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप भारत लगातार लगाता रहा है।

शांति के रखवाले या जंग के व्यापारी

अमेरिका, वैश्विक राजनीति में स्वयं को लोकतंत्र और शांति का समर्थक बताता है। लेकिन कई मौकों पर उसकी नीतियां टकराव को बढ़ावा देती नजर आई हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को भारी सैन्य और वित्तीय सहायता दी। इससे युद्ध लंबा खिंचा। रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने का प्रयास किया गया, लेकिन इससे ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है। ईरान परमाणु समझौते से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बाहर निकलने से टकराव और बढ़ गया। अमेरिका दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को हथियार देना और भारत के आतंरिक मामलों में टिप्पणी कभी-कभी संदेह पैदा करती है।

क्या डोनाल्ड ट्रंप जंग को बढ़ावा दे रहे?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कई अंतरराष्ट्रीय टकराव या तो तेज हुए या उनके समाधान की दिशा में गंभीर कोशिशें नहीं हुईं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान परमाणु समझौता रद्द करना, उत्तर कोरिया के साथ 'फोटो-ऑप' कूटनीति, लेकिन वास्तविक समाधान नहीं, यूक्रेन को हथियार आपूर्ति के मुद्दे को घरेलू राजनीति (बाइडेन के खिलाफ जाँच) के लिए इस्तेमाल करना। कुल मिलाकर वर्तमान समय में जो दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं वह यह दर्शाते हैं कि शक्ति प्रदर्शन केवल सैन्य हथियारों से नहीं, बल्कि कूटनीतिक रणनीतियों, तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक गठबंधनों से भी संभव है। भारत जैसी उभरती शक्ति ने यह दिखाया है कि विकास, विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और वैश्विक नीति में संतुलन बना कर भी विश्व में प्रभाव जमाया जा सकता है। शांति की तलाश और सहयोग की भावना के बिना शक्ति प्रदर्शन विनाश की ओर ही ले जाएगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश रणनीतिक संयम, सार्थक संवाद और बहुपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता दें।

जगन्नाथ रथयात्रा हादसा प्रबंधन की भूल का परिणाम

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

धार्मिक उत्सवों में दुर्घटनाओं का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज कुंभ मेले में और इसी साल जून माह में बैंगलुरु में आईपीएल मैच में मची भगदड़ की स्मृतियां विलोपित भी नहीं हो पाई थीं कि पुरी में चल रहे भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में भगदड़ मचने से तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। गुंडिचा मंदिर के पास घटी यह घटना पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। मंदिर में प्रवेश का रास्ता केवल एक था, बाहर जाने का मार्ग बंद कर दिया था, क्योंकि वहां से वीआईपी लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। आम भक्तों के लिए बाहर आने का दूसरा कोई मार्ग नहीं था। इसी समय मंदिर में दो ट्रक लकड़ी और अनुष्ठान सामग्री से भरे इसी संकीर्ण मार्ग से भीतर भेज दिए गए। ट्रकों के कारण भीड़ में अफरा-तफरी मच गई और हादसा घट गया। साफ है, प्रशासनिक प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते श्रद्धालु हादसे के शिकार हो गए। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुरक्षा की चूक के लिए क्षमा मांगते हुए पुरी के कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर और एसपी विनीत अग्रवाल का अविलंब स्थानांतरण कर दिया। स्थानांतरण कोई सजा नहीं होती। वास्तव में कुंभ मेले में और आईपीएल क्रिकेट मैच में हुए हादसों से प्रशासन को सबक लेने की जरूरत थी, जिससे रथयात्रा में भगदड़ से बचा जाए।

भारत में पिछले डेढ़ दशक के दौरान मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों में उम्मीद से कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। जिसके चलते दर्शन-लाभ की जल्दबाजी व कुप्रबंधन से उपजने वाली भगदड़ व आगजनी का सिलसिला हर साल इस तरह के धार्मिक मेलों में देखने में आ रहा है। स्पष्ट है, प्रत्येक कुंभ में जानलेवा घटनाएं घटती रहने के बावजूद शासन-प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिए। धर्म स्थल हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम कम से कम शालीनता और आत्मानुशासन का परिचय दें। किंतु इस बात की परवाह आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं होती, अतएव उनकी जो सजगता घटना के पूर्व सामने आनी चाहिए, वह अक्सर देखने में नहीं आती ? लिहाजा आजादी के बाद से ही राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र उस अनियंत्रित स्थिति को काबू करने की कोशिश में लगा रहता है, जिसे वह समय पर नियंत्रित करने की कोशिश करता तो हालात कमोबेश बेकाबू ही नहीं हुए होते? अतएव देखने में आता है कि आयोजन को सफल बनाने में जुटे अधिकारी भीड़ के मनोविज्ञान का आकलन करने में चूकते दिखाई देते हैं।

रथयात्रा की तैयारियों के लिए कई हजार करोड़ की धनराशि खर्च की जाती है। जरूरत से ज्यादा प्रचार करके लोगों को यात्रा के लिए प्रेरित किया जाता है। फलतः जनसैलाब इतनी बड़ी संख्या में उमड़ गया कि सारे रास्ते पैदल भीड़ से जाम हो गए। इसी बीच लापरवाही यह रही कि बाहर जाने के रास्ते को नेता और नौकरशाहों के लिए आरक्षित कर दिया गया और दो ट्रक आम रास्ते से मंदिर की ओर भेज दिए। इस चूक ने घटना को अंजाम दे दिया। जो भी प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकि उपाय किए गए थे, वे सब व्यर्थ साबित हुए। क्योंकि उन पर जो घटना के भयावह दृश्य दिखाई देने लगे थे, उनसे निपटने का तात्कालिक कोई उपाय ही संभव नहीं रह गया था। ऐसी लापरवाही और बदइंतजामी सामने आना चकित करती है। दरअसल रथयात्रा में जो भीड़ उमड़ी थी, उसके आवागमन के प्रबंधन के लिए जिस प्रबंध कौशल की जरुरत थी, उसके प्रति घटना से पूर्व सर्तकता बरतने की जरूरत थी? इसके प्रति प्रबंधन अदूरदर्शी रहा। मेलों के प्रबंधन की सीख हम विदेशी साहित्य और प्रशिक्षण से लेते हैं। जो भारतीय मेलों के परिप्रेक्ष्य में कतई प्रासंगिक नहीं है। क्योंकि दुनिया के किसी अन्य देश में किसी एक दिन और विशेष मुहूर्त के समय लाखों-करोड़ों की भीड़ जुटने की उम्मीद ही नहीं की जाती? बावजूद हमारे नौकरशाह भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण, लेने खासतौर से योरुपीय देशों में जाते हैं। प्रबंधन के ऐसे प्रशिक्षण विदेशी सैर-सपाटे के बहाने हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे प्रबंधनों के पाठ हमें खुद अपने देशज ज्ञान और अनुभव से सिखने होंगे।

प्रशासन के साथ हमारे राजनेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और आला अधिकारी भी धार्मिक लाभ लेने की होड़ में व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं। इनकी वीआईपी व्यवस्था और यज्ञ कुण्ड अथवा मंदिरों में मूर्तिस्थल तक हो हर हाल में पहुंचने की रुढ़ मनोदशा, मौजूदा प्रबंधन को लाचार बनाने का काम करती है। जो इस रथयात्रा में देखने में आई है। आम श्रद्धालुओं के बाहर जाने का रास्ता इन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित कर दिया गया था। नतीजतन भीड़ ठसाठस के हालात में आ गई और दुर्घटना घट गई। दरअसल दर्शन-लाभ और पूजापाठ जैसे अनुश्ठान अशक्त और अपंग मनुष्य की वैशाखी हैं। जब इंसान सत्य और ईश्वर की खोज करते-करते थक जाता है और किसी परिणाम पर भी नहीं पहुंचता है तो वह पूजापाठों के प्रतीक गढ़कर उसी को सत्य या ईश्वर मानने लगता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है। यथार्थवाद से पलायन अंधविश्वास की जड़ता उत्पन्न करता है। भारतीय समाज में यह कमजोरी बहुत व्यापक और दीर्घकालीक रही है। जब चिंतन मनन की धारा सूख जाती है तो सत्य की खोज मूर्ति पूजा और मुहूर्त्त की शुभ घड़ियों में सिमट जाती है। जब अध्ययन के बाद मौलिक चिंतन का मन-मस्तिष्क में ह्रास हो जाता है तो मानव समुदाय भजन-कीर्तन में लग जाता है। यही हश्र हमारे पथ-प्रदर्शकों का हो गया है। नतीजतन पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा मौतें भगदड़ की घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में उन श्रद्धालुओं की हो रही हैं, जो ईश्वर से खुशहाल जीवन की प्रार्थना करने धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं।

मीडिया इसी पूजा-पाठ का नाट्य रूपांतरण करके दिखाता है, यह अलौकिक कल्पावाद, धार्मिक आस्था के बहाने व्यक्ति को निश्क्रिय व अंधविश्वासी बनाता है। यही भावना मानवीय मस्तकों को यथास्थिति में बनाए रखने का काम करती है और हम ईश्वरीय अथवा भाग्य आधारित अवधारणा को भाग्य और प्रतिफल व नियति का कारक मानने लग जाते हैं। दरअसल मीडिया, राजनेता और बुद्धिजीवियों का काम लोगों को जागरूक बनाने का है, लेकिन निजी लाभ का लालची मीडिया, लोगों को धर्मभीरू बना रहा है। राजनेता और धर्म की आंतरिक आध्यात्मिकता से अज्ञान बुद्धिजीवी भी धर्म के छद्म का शिकार होते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि पिछले दो दशक के भीतर मंदिर हादसों में लगभग 5000 से भी ज्यादा भक्त मारे जा चुके हैं। बावजूद श्रद्धालु हैं कि दर्शन, आस्था, पूजा और भक्ति से यह अर्थ निकालने में लगे हैं कि इनको संपन्न करने से इस जन्म में किए पाप धुल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। गोया, पुनर्जन्म हुआ भी तो श्रेष्ठ वर्ण में होने के साथ आर्थिक रूप से समृद्ध व वैभवशाली होगा। परंतु इस तरह के खोखले दावों का दांव हर मेले में ताश के पत्तों की तरह बिखरता दिखाई दे रहा है। जाहिर है, धार्मिक दुर्घटनाओं से छुटकारा पाने की कोई उम्मीद निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रही है?

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दे रहे छत्तीसगढ़ को विकास के नये आयाम

(पेज 1 का शेष)

महिलाओं और युवाओं को सौगात

महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को सशक्त बनाते हुए उनकी स्वरोजगार और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी मूर्तरूप दिया गया। वहीं, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण के नये केंद्र खोले गये। हाल ही में रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में आयोजित रोजगार मेलों से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं।

भ्रष्टाचार पर सख्ती

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कार्यकाल भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदमों के लिए भी चर्चा में है। सत्ता संभालते ही उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच को गति दी। कोयला, शराब, रेत खनन से लेकर तबादला उद्योग तक, हर घोटाले की परतें खुल रही हैं। ईडी और एसीबी की कार्रवाई को मुख्यमंत्री का अप्रत्यक्ष समर्थन माना जा रहा है। उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि साय का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी या नेता को बख्शा नहीं जाये।

कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता

हालांकि, प्रदेश की कानून व्यवस्था अभी भी चुनौती बनी हुई है। राज्य के कई जिलों से चोरी, डकैती, छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे जनता आहत है। बीते दिनों दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़ से लूट, अपहरण और हत्या की खबरें आईं। मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई। हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

नक्सलवाद पर नकेल

नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में भी साय सरकार ने कड़ी रणनीति अपनाई है। बीते महीनों में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से कई शीर्ष नक्सली मारे गये। वहीं, surrendered नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज की भी घोषणा की गई। बस्तर में सड़क निर्माण, मोबाइल नेटवर्क विस्तार और आदिवासी युवाओं के लिए भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं, ताकि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

विकास के नये संकेत

हाल ही में मुख्यमंत्री ने रायपुर और बिलासपुर में फ्लाईओवर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना मेरा संकल्प है। आने वाले दिनों में हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी योजनाएं लाएंगे, जिससे प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। ग्रामीण अंचलों में किसानों का मानना है कि अगर खरीफ सीजन में भी खाद-बीज की आपूर्ति समय पर हो जाये और समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहे, तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वहीं, शहरी वर्ग चाहता है कि बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगे। महिला संगठनों का कहना है कि छेड़छाड़, दुष्कर्म और घरेलू हिंसा के मामलों में तेज सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

राहत की सांस ले रही प्रदेश की जनता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 20 महीनों के कार्यकाल में यह साबित किया है कि वे निर्णय लेने में हिचकते नहीं हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती, विकास योजनाओं की गति और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा का मजबूत तंत्र उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। परंतु कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे हैं, जिन पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की जनता फिलहाल राहत की सांस ले रही है, लेकिन उसे उम्मीद है कि "विकास के नये आयाम तभी सार्थक होंगे जब आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करेगा और न्याय की उम्मीद लेकर दर-दर न भटके।

छत्तीसगढ़

गढ़ रहा उद्योगों की स्थापना के नए अवसर

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

"अब उद्यमी बनने की राह हुई आसान"

सिंगल विंडो सिस्टम 2.0

- **पोर्टल के माध्यम** से 16 से अधिक विभागों की 100 से अधिक सुविधा
- **उद्योगों की स्थापना** में सहयोग, युवाओं को रोजगार के मौके
- **ऑफलाइन मोड में** किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं
- पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों का **क्लीयरेंस**
- **ई-चालान** के माध्यम से पेमेंट की सुविधा
- **सिंगल क्लिक पर** देखी जा सकती है आवेदन की स्थिति

R.O. No. :13313/1

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprog.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेपन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)